1975-76 और 1976-77 में उवरकों का अनुमानित खपत और उत्पादन के आंकड़ निम्नलिखित हैं :—

(लाख मी० टन में)

वर्ष	उत्पादन		खपत	
	एन	पी	एन	पी
1975-76	15.35	3.20	20.32	4.45
1976-77	19.0	4.80	24.77	6.7

नाइट्रोजनस और फास्फेटिक उर्वरकों के बारे में मांग का पर्याप्त भाग देशी उत्पादन से पूरा किया जाता है और देशी उपलब्धता और मांग के बीच में अन्तर को पूरा करने के लिए अपेक्षित आयात द्वारा प्रबन्ध किया जाता हैं।

देशी उपलब्धता और उर्वरकों के लिए मांग के बीच अन्तर को कम करने के लिए नए उर्वरक संयंत्रों की स्थापना करने के लिए एक बड़े कार्यक्रम का भी कार्यान्वय किया जा रहा है।

शिक्षित बेरोजगारों को पैट्रोल पम्पों और गैस एजेन्सियों का आवंटन

3187. **श्री महीलाल** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 और 1976-77 में भारतीय तेल निगम ने देश भर में प्रत्येक शहर में कुल कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को पैट्रोल, डीजल पम्पों और कुकिंग गैस की अलग अलग कितनी एजेन्सियां दी ;

(ख) उनमें से कितने पैट्रोल, डीजल पम्पों और गैस की एजेंसियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार युवकों को दी गई और आवेदन पत्र अभी विचारधीन पड़े हैं ; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जब तक आरक्षित कोटा पूरा नहीं हो जाता, तब तक उपर्युक्त एजेन्सियां केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति के युवकों को ही दी जायें ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग). अक्तूबर 1969 तक इंडियन आयल कारपोरेशन (आई० ओ० सी०) वाणिज्यिक विचारधाराओं पर अपनी एजेंसियां दे रहा था। नवम्बर 1969 में ये नीति बदल दी गई थी और आई० ओ० सी० की डीलरशिप एजेंसियां निम्न आय वर्ग परिवारों से सम्बन्धित बेरोजगार स्नातकों/इंजीनियरों आदि को दी जाती थी। यह नीति नवम्बर 1971 तक चलती रही। दिसम्बर 1971 में हुए युद्ध के पश्चात इस नीति का अतिक्रमण किया गया और एक ऐसी नीति खोज निकाली गई जिसके द्वारा आई० ओ० सी० की डिलरशिप और एजेंसियां अपंग प्रतिरक्षा कार्मिकों, युद्ध में मृत सैनिकों की विधवाओं, युद्ध में मारे गये अथवा गुमशुदा सैनिकों के आश्रितों और

भूतपूर्व सैनिकों को रक्षा मंत्रालय के पुनर्वास महानिदेशक की सिफारिश पर दी जाती थीं। इस योजना को 1-2-1975 से अस्थगित कर दिया गया है। वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 के दौरान शिक्षित बेरोजगारों को एजेंसियां प्रदान करने की आई० ओ० सी० की कोई नीति नहीं थी। 1-1-1974 से लागू अपनी नीति के अनुसार आई० ओ० सी० अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये ('ख' स्थान के केन्द्रों को छोड़ कर अपनी 25% एजेंसियां आरक्षित कर रहा है। 31-3-1977 की यथास्थिति के अनुसार आई० ओ० सी० ने 1-1-1974 से अब तक खोले गये नये 49 बिक्री केन्द्रों में से 19 'क' स्थान वाले फुटकर बिक्री केन्द्र पैट्रोल और डीजल पम्प) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को दी हैं। इसी प्रकार से नई खाना पकाने की गैस की 71 एजेंसियों में से (ऐसी एजेंसियों को छोड़कर जिन्हें उप-वितरकशिप से वितरकशिप में बदल दी गयी और पुनर्वास महानिदेशालय के नामितों को आवंटित की गई) 18 एजेंसियां इस अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को दी गई थी। अतः आई० ओ० सी० अब तक अनुसूचित जातियों।जनजातियों के लिये निर्धारित आरक्षण के अनुसरण में उन्हें एजेंसियों के आवंटन को सुनिश्चित कर सका है।

Bribing of voters in Sathankulam Assembly Constituency in Tamil Nadu

3188. SHRI K. T. KOSALRAM: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that in recent Assembly elections in Tamil Nadu, some of the contestants in Sathankulam Assembly Constituency in Tirunelveli District, indulged in large scale bribing of voters;

(b) if so, whether some of the persons involved in the bribing were caught and handed over to the police but were later on let out on the plea that it is a non-cognizable offence under the Penal Code even though the offence was triable by a First Class Magistrate; and

(c) if so, whether Government propose to amend the Penal Code to make such an offence a cognizable offence to put an end to such malpractices of influencing the voters by the contestants?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) and (b). The Election Commission has received a complaint that one of the contesting candidates had distributed money to the voters. The Chief Electoral Officer, Tamil Nadu, has been asked by the Election Commission to enquire into the allegation and send a report. The report is still awaited.

(c) No such proposal is under consideration at present.

Double Railway Line for Sealdah Bongaon and Bandel Katwa

3189. SHRI SAUGATA ROY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government propose to start work on doubling the Sealdah-Bongaon and Bandel Katwa lines soon; and

(b) if so, details thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) and (b). While there is no proposal to double the Bandel-Katwa section, as regards doubling a portion of Sealdah-Bongaon section, the matter is under correspondence with the Ministry of Finance regarding financial arrangements.